between the border outposts, intensification of patrolling both on the land and the riverine border, accelerated programme of construction of border roads and fencing, increase in the number of O P Towers, provision of surveillance equipments etc. The matter has also been taken up with the Government of Bangladesh on various occasions. The progress of these measures is reviewed regularly at various levels. The Government, however, do not propose to appoint a high powered committee for this purpose.

Proposals to make public prosecutors office independent

6213. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to make the Public Prosecutor's office independent of the State Governments/ Union Territories to check accumulation of cases in courts;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government have since taken any final view in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) There is no proposal before the Government to make the Public Prosecutor's Office independent of the State Governments/ Union Territories.

(b) and (c) Does not arise.

Formation of A Development Council for the Western Part of Orissa

6214. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for the formation of a Development Council for the Western parts of Orissa; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) No. Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

बम्बई का नाम बदल कर मुम्बई किया जाना

6215. श्री संघ प्रिय गौतम:

डा॰ बापू कालदाते:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य की राजधानी का नाम बम्बई से बदलकर मुम्बई कर देने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव पिछले तीन वर्षों से केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ा था और तत्कालीन सरकार इसका नाम बदलने के लिए सहमत नहीं हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगी और इसे अब तक स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) मामला विचाराधीन है।

केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक

6216. श्री ईश दत्त यादव:
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय हिन्दी समिति की चौबीसवीं बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद): (क) केन्द्रीय हिन्दी समिति की चौबीसवीं बैठक दिनांक 25 जून, 1994 को हुई।